संजय कुमार अग्रवाल अध्यक्ष Sanjay Kumar Agarwal Chairman







भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Indirect Taxes & Customs

22nd April, 2024

DO No. 17/News Letter/CH(IC)/2024

Dear Colleague,

I attended the 25th Asia Pacific Regional Heads of Customs Administration (RHCA) Conference held in Sydney last week, where India was unanimously affirmed of its position, both for Policy Commission and Finance Committee of the World Customs Organization (WCO) for the duration 2024-26. Further, India's proposal of NACIN Palasamudram as a Customs Training Centre was recognized and supported at the forum. On the sidelines of the Conference, Indian Customs and Australian Border Force signed the AEO Mutual Recognition Arrangement – a major trade facilitation measure for Indian importers and exporters. The positive culmination of India's efforts in these areas not only enhances India's standing within the International trade community but also reaffirms India's resolve to WCO's theme – Customs Engaging Traditional and New Partners with Purpose.

It is heartening to note that the pan-India thematic Audit as envisaged by the All India Coordination Committee, has commenced. In this regard, a sub-Committee headed by Sh. Hardeep Batra, Commissioner CGST Audit Ludhiana and comprising officers from State GST have developed a 'Common Minimum Audit Plan for the banking sector'. This audit plan, released this month, provides guidelines to aid audit officers, both from the Centre and the States, to carry out Thematic Audit in an efficient, focussed, transparent and coordinated manner. This will be another stellar example of the synergies of the Centre and the States in the implementation of GST.

Three officers team from DG Systems led by Sh. Neeraj Kansal, Pr. ADG participated in the National Critical Information Infrastructure Security Exercise (CII SECEX: 2024) organised by the National Critical Information Infrastructure

Protection Centre (NCIIPC). Amongst nearly 500 participants, CBIC was part of the team which stood 2nd out of a total of 35 teams. Sh. Jitendra Bansal, Assistant Director and designated Dy. CISO, received the prize from Pr. Scientific Advisor to GOI on behalf of CBIC. Undoubtedly, the professional competence of CBIC exudes confidence!

In an interesting and dramatic case booked by DRI Mumbai, a gang of wildlife traffickers was intercepted in Nashik district while seeking prospective buyers for body parts of Bengal Monitor Lizard and soft corals. The DRI officers kept on close heels of the traffickers, who kept on changing locations for a few hours, finally deciding to exchange at a tribal hamlet with an extremely harsh terrain consisting of thorny scrubland with no scope for movement of four-wheelers. At the time of exchange, when the DRI team confronted the gang members, they were immediately surrounded by a mob of locals. Braving the mob, the officers finally apprehended the traffickers after a chase on foot. The officers managed to recover 781 Hatha Jodis and 19.6 kg of soft corals which are listed under Schedule–I of the Wildlife (Protection) Act, 1972. Excellent execution by the officers!

Until next week!

Yours sincerely,

(Sanjay Kumar Agarwal)

Sijly

All Officers and Staff of the Central Board of Indirect Taxes & Customs.









भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क Government of India Ministry of Finance Department of Revenue

Central Board of Indirect Taxes & Customs

22 अप्रैल, 2024

DO No. 17/News Letter/CH(IC)/2024

प्रिय सहस्रभी

मैंने पिछले सप्ताह सिडनी में आयोजित 25वें एशिया रेजिनल हेड्स ऑफ़ कस्टमस एडिमिनिस्ट्रेशन (RHCA) सम्मेलन में भाग लिया, जहां 2024-26 की अविध के लिए विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) की वित्त सिमिति और नीति आयोग के लिए सर्वसम्मिति से भारत की स्थिति को स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा, सीमा शुल्क प्रशिक्षण केंद्र के रूप में NACIN पालासमुद्रम के भारत के प्रस्ताव को मंच पर मान्यता दी गई और उसका समर्थन किया गया। सम्मेलन के दौरान, भारतीय सीमा शुल्क और ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल ने AEO (एईओ) म्युचअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट पर हस्ताक्षर किए - जो भारतीय आयातकों और निर्यातकों के लिए एक प्रमुख व्यापार सुविधा उपाय है। इन क्षेत्रों में भारत के प्रयासों की सकारात्मक परिणाम न केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय के मध्य भारत के औदे को बढ़ाता है, बल्कि WCO की थीम— "Customs Engaging Traditional and New Partners with Purpose" पर भारत के संकल्प की भी पृष्टि करता है।

मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि अखिल भारतीय समन्वय सिमित द्वारा परिकल्पित किया गया पैन- इंडिया थीमेटिक ऑडिट शुरू हो गया है। इस संबंध में, श्री हरदीप बत्रा, आयुक्त सीजीएसटी ऑडिट लुधियाना की अध्यक्षता में जिसमे राज्य जीएसटी के अधिकारी भी शामिल है, ने 'बैंकिंग क्षेत्र' के लिए सामान्य न्यूनतम ऑडिट योजना' विकसित की है। यह ऑडिट योजना इसी माह जारी की गई है, जो कि, केंद्र और राज्य दोनों के ऑडिट अधिकारियों को कुशल, केंद्रित, पारदर्शी और समन्वित तरीके से थीमेटिक ऑडिट करने में सहायता करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करती है। यह जीएसटी के कार्यान्वयन में केंद्र और राज्यों के तालमेल का एक और शानदार उदाहरण होगा।

श्री नीरज कंसल, प्र. एडीजी के नेतृत्व में डीजी सिस्टम्स के तीन अधिकारियों की टीम ने नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (NCIIPC) द्वारा आयोजित नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एक्सरसाइज (CII SECEX :2024) में भाग लिया। लगभग 500 प्रतिभागियों के बीच, सीबीआईसी उस टीम का हिस्सा थी जो कुल 35 टीमों में से दूसरे स्थान पर रही। श्री जितेंद्र बंसल, सहायक निदेशक और उपप्रधान सीआईएसओ (CISO) को सीबीआईसी की ओर से भारत सरकार के प्र. वैज्ञानिक सलाहकार से पुरस्कार मिला। निःसंदेह, सीबीआईसी की व्यावसायिक क्षमता से आत्मविश्वास झलकता है!

डीआरआई मुंबई द्वारा दर्ज किए गए एक दिलचस्प मामले में, वन्यजीव तस्करों के एक गिरोह को बंगाल मॉनिटर छिपकली के शरीर के अंगों और नरम मूंगों के लिए संभावित खरीदारों की तलाश करते हुए नासिक ज़िले में पकड़ा गया था। डीआरआई अधिकारियों ने तस्करों पर कड़ी नज़र रखी, जो कुछ घंटों तक स्थान बदलते रहे, अंततः एक आदिवासी बस्ती में आदान-प्रदान करने का निर्णय लिया, जो बेहद कठोर इलाका था, जिसमें कांटेदार झाड़ियाँ थीं और चार पिहया वाहनों की आवाजाही की कोई गुंजाइश नहीं थी। आदान-प्रदान के समय, जब डीआरआई टीम ने गिरोह के सदस्यों का सामना किया, तो वे तुरंत स्थानीय लोगों की भीड़ से घिर गए। भीड़ का सामना करते हुए अधिकारियों ने आखिरकार पैदल पीछा करने के बाद तस्करों को पकड़ लिया। अधिकारी 781 हत्था जोड़ी और 19.6 किलोग्राम नरम मूंगा बरामद करने में कामयाब रहे, जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-। के तहत सूचीबद्ध हैं। अधिकारियों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन!

अगले सप्ताह तक ।

भवदीय,

संजय समार

(संजय कुमार अग्रवाल)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण।